नईदुनिया



विदेशी भुगतान पर 10 लाख रुपए की ईडीएफ शर्त : आरबीआई

नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सेवा निर्यातकों के लिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फार्म (ईडीएफ) दाखिल करने संबंधी 10 लाख रुपये की सीमा पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि यह सीमा कुल प्राप्तियों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिगत आवक प्रेषण (इनवार्ड रेमिटेंस) पर लागू होगी।

सेवा निर्यातकों को आरबीआई से राहत: ईडीएफ फाइलिंग में प्रति रेमिटेंस 10 लाख की सीमा स्पष्ट

इस कदम से नए विदेशी मुद्रा ढांचे के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को लेकर निर्यातकों को काफी स्पष्टता मिली है और उनके लिए अनुपालन (कंप्लायंस) आसान होगा। आरबीआई द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के अनुसार, निवासी व्यक्तियों के अलावा अन्य सेवा निर्यातकों को ईडीएफ तभी दाखिल करना होगा जब किसी एक व्यक्तिगत आवक प्रेषण का मूल्य 10 लाख रुपये या इसके बराबर विदेशी मुद्रा से अधिक हो। यह घोषणा निर्यातकों के खाते में राशि जमा होने से पहले करनी होगी।

यह स्पष्टीकरण रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2026 के तहत आया है, जिसे 2 नवंबर को अधिसूचित किया गया था और 1 अक्टूबर से प्रभावी था। केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया कि 1 अक्टूबर से पहले जारी किए गए सेवा निर्यात चालानों के लिए ईडीएफ की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही भुगतान उस तारीख के बाद प्राप्त हो।

सेवाओं का निर्यात करने वाले निवासी व्यक्तियों को अलग से ईडीएफ दाखिल करने से छूट दी गई है; उनके अधिकृत डीलर (एडी) बैंक को आवश्यक जानकारी प्रदान करने पर इसे स्वत: जमा माना जाएगा। अधिकृत डीलर बैंक गैर-व्यक्तिगत निर्यातकों से 10 लाख रुपये तक के आवक प्रेषण के लिए या निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किसी भी राशि के लिए ईडीएफ की मांग नहीं कर सकते। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव में, आरबीआई ने घोषणा की है कि साफ्टवेयर निर्यात के लिए पहले आवश्यक रहा साफ्टेक्स फार्म 1 अक्टूबर से बंद कर दिया गया है।

अब घरेलू शुल्क क्षेत्र के साफ्टवेयर निर्यातक किसी भी एडी बैंक या साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया (एसटीपीआई) में ईडीएफ जमा कर सकते हैं, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से काम करने वाले इसे संबंधित डेवलपमेंट कमिश्नर के पास जमा कर सकते हैं।

न्यूज ब्रीफ

भारत-बुल्गारिया ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की



नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के दौरे पर आईं बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा के साथ बैठक कर द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस बातचीत के दौरान बुल्गारिया में व्यापार बढ़ाने और भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने दिसंबर की शुरुआत में सोफिया में होने वाले बुल्गारिया-भारतीय व्यापार मंच के माध्यम से बातचीत जारी रखने की संभावना पर भी विचार किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बुल्गारिया के विदेश मंत्री डा. वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा के साथ सार्थक बैठक की। उन्होंने बताया कि भारत-बुल्गारिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव सहित आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने जारी बयान में कहा कि भारत और बुल्गारिया के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को मजबूत करने और साझेदारी के नए रास्ते तलाशने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इससे पहले बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेत्रोवा ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। पेत्रोवा की नई दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगी। बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के निमंत्रण पर 20-22 नवंबर तक भारत की आधिकारिक दौरे पर हैं, जो पिछले 17 वर्षों में किसी बल्गेरियाई विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है।

सुरक्षा को लेकर हुंडई वरना को मिली 5-स्टार रेटिंग



नई दिल्ली। हुंडई की लोकप्रिय सेडान वरना कार को भारत एनसीएपी (भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) के क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वरना ने एडल्ट और चाइल्ड आक्यूपेंट प्रोटेक्शन, यानी यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दोनों टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इससे पहले, अक्टूबर 2023 में भी वरना को ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी थी, जिससे यह भारत में बनी हुंडई की पहली कार बनी थी जिसने यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत एनसीएपी द्वारा नवंबर 2026 में जारी किए गए क्रैश टेस्ट के नतीजों के अनुसार, वरना को एडल्ट आक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 28.22 पाइंट मिले हैं। वहीं, चाइल्ड आक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कार ने 49 में से 44 पाइंट हासिल किए, इस तरह दोनों कैटेगरी में इसे सर्वोच्च 5-स्टार रेटिंग मिली। टेस्ट के लिए वरना के 1.5 टर्बो जीडीआई डीसीटी और 1.5 एमपीआईआईवीटी माडल का इस्तेमाल किया गया था। एडल्ट आक्यूपेंट प्रोटेक्शन के तहत फ्रंटल आफसेट डिफार्मेबल बैरियर टेस्ट और साइड मूवेबल डिफार्मेबल बैरियर टेस्ट में कार ने शानदार प्रदर्शन किया। चाइल्ड आक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में भी कार ने डायनामिक स्कोर में पूरे 24 में से 24 पाइंट हासिल किए, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए इसकी उत्कृष्ट क्षमता को दर्शाता है।

बजाज आटो ने किए डोमिनार 400 में महत्वपूर्ण अपग्रेड

नई दिल्ली। वाहन निर्माता कंपनी बजाज आटो अब मोटर साइकिल डोमिनार 400 में भी महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं। हाल ही में बाइक के 350सीसी इंजन को नए कर ढांचे के अनुरूप अपडेट किया गया था। यह वही उन्नत टीएफटी स्क्रीन है जो आजकल पल्सर फैमिली में भी दी जा रही है। यह 5-इंच का टीएफटी क्लस्टर सेगमेंट में सबसे बेहतरीन में से एक है, जो एंड्राइड फोन की स्क्रीन बंद होने पर भी गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है। इसमें डाक्यूमेंट स्टोरेज, लैप टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशन और अन्य उपयोगी फीचर्स भी मिलते हैं। स्क्रीन काफी ब्राइट है और इसमें डे-नाइट थीम के साथ-साथ आटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट की सुविधा भी है। इसके साथ ही, कंपनी ने डोमिनार 400 की स्पेक शीट में टायर प्रेशर मानिटरिंग सिस्टम को भी शामिल किया है, जिससे यह टीपीएमएस फीचर पाने वाली बजाज की पहली मोटरसाइकिल बन गई है। यह सीधे क्लस्टर पर टायर का प्रेशर दिखा सकेगी। टीएफटी क्लस्टर की मदद से राइडर्स अलग-अलग राइड मोड्स के बीच स्विच कर सकेंगे और ट्रैक्शन कंट्रोल व रियर एबीएस को आन या आफ भी कर सकेंगे।



शेयर बाजार में दीर्घकालिक निवेश पर जोर : सीईए

शुरुआती अति-वित्तपोषण से बचें ; खुदरा डेरिवेटिव में भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की

नई दिल्ली

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने पूंजी बाजारों को लंबी अवधि के निवेश और रोजगार सृजन करने वाले व्यवसायों के लिए धन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। उन्होंने आगाह किया कि विकास के शुरुआती चरणों में अत्यधिक धन लगाने से भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाएँ कमजोर हो सकती हैं। सीआईआई फाइनैंसिंग समिट में बोलते हुए नागेश्वरन ने जोर दिया कि पूंजी बाजारों को बचत जुटाने और उन व्यवसायों पर केंद्रित होने की अपनी मूल भूमिका पर लौटना चाहिए जो विनिर्माण करते हैं, बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं और रोजगार सृजित करते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पिछले चार दशकों में यह संबंध उलट गया है, और फाइनैंसिंग अब उत्पादन की सुविधा प्रदान करने के बजाय प्रमुख भूमिका में आ गया है। उनके अनुसार, भारत की वित्त व्यवस्था की मुख्य परीक्षा यह होनी चाहिए कि क्या उद्यमी 20 साल की परियोजना के लिए आसानी से धन जुटा सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कार्पोरेट बान्ड बाजार की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मात्र 16 प्रतिशत हिस्सेदारी पर चिंता जताई, जबकि शेयर बाजार पूंजी जीडीपी के 130 प्रतिशत के करीब है।

उन्होंने जोर दिया कि फैक्टरियों, पावर ग्रिडों, बंदरगाहों और फैब्रिकेशन संयंत्रों जैसी परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। नागेश्वरन ने इक्विटी डेरिवेटिव में बढ़ती खुदरा भागीदारी से उत्पन्न जोखिमों को भी उजागर किया। आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों में लगभग 93 प्रतिशत खुदरा ट्रेडर्स को इक्विटी डेरिवेटिव्स में कुल 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि 75 प्रतिशत से अधिक खुदरा ट्रेडर्स की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम थी, फिर भी घाटे के बावजूद वे ट्रेडिंग जारी रखते हैं। नागेश्वरन ने इसे मानव व्यवहार से जुड़ी समस्या बताया, जिसे अब तेज़ ट्रेडिंग टूल और बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल नियमों से नहीं, बल्कि बाजार सहभागियों, वित्तीय संस्थानों और इंटरमीडिएटरीज को भी जिम्मेदारी लेनी होगी।



टाटा टेक्नोलाजीज के शेयर पर ब्रोकरेज सतर्क, 13 फीसदी गिरावट का अनुमान



मुंबई। टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलाजीज ने वित्त वर्ष 2030 तक अपने कारोबार को 1.1 से 1.3 अरब डालर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी रणनीति प्रस्तुत की है। हाल ही में निवेशक दिवस पर पेश की गई इस योजना में साफ्टवेयर, एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग सेवाओं को प्रमुख विकास इंजन के रूप में रेखांकित किया गया है। हालांकि, इन बुलंद लक्ष्यों के बावजूद, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इसके शेयर को बेचने की सलाह दी है, यह मानते हुए कि मौजूदा बाजार मूल्य में भविष्य की अधिकांश वृद्धि पहले ही शामिल हो चुकी है। टाटा टेक्नोलाजीज ने वित्त वर्ष 2027 से 2030 के बीच राजस्व में सालाना 15-20 फीसदी की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। कंपनी केवल कारोबार के आकार पर नहीं, बल्कि मुनाफे में भी सुधार पर केंद्रित है। इसका आपरेटिंग मार्जिन वित्त वर्ष 2026 के 15.5 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही तक 17 फीसदी और वित्त वर्ष 2030 तक 20 फीसदी से अधिक करने की योजना है। साफ्टवेयर कारोबार कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र है, जो वित्त वर्ष 2021 के 48 लाख डालर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 6.4 करोड़ डालर हो गया है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 में पुराने साफ्टवेयर कारोबार से 10 करोड़ डालर का राजस्व हासिल करना और अगले तीन वर्षों में इसमें अतिरिक्त 10 करोड़ डालर जोड़ना है। एयरोस्पेस क्षेत्र में भी पिछले पांच वर्षों में लगभग 40 फीसदी की सालाना वृद्धि देखी गई है। टाटा टेक्नोलाजीज वित्त वर्ष 2028 तक इस कारोबार को 10 करोड़ डालर के वार्षिक राजस्व स्तर तक पहुंचाना चाहती है, जिसके बाद वित्त वर्ष 2030 तक इसमें 25-30 फीसदी सालाना वृद्धि का अनुमान है। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक वाहन उद्योग में इलेक्ट्रानिक्स और साफ्टवेयर की बढ़ती भूमिका, साथ ही एआई का उपयोग, कंपनी के लिए नए अवसर पैदा करेगा और लागत दक्षता बढ़ाएगा ।

ईवी चार्जिंग में डिस्काम का असहयोग: पीएम सलाहकार

तरुण कपूर ने नोडल अधिकारी, उच्च लागत व कम उपयोग पर जताई चिंता



नई दिल्ली

प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के अपर्याप्त सहयोग पर गंभीर चिंता जताई है। सायएम सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत के सरप्लस बिजली उत्पादन के बावजूद, डिस्काम ईवी को बिजली खपत के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में नहीं देख रही हैं।

कपूर ने हर डिस्काम में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की वकालत की, ताकि चार्जिंग केंद्र संचालकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। कपूर ने डिस्काम के गैर-सहयोगी रवैये की आलोचना की, विशेषकर 200 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के ग्रिड कनेक्शन पर मोटी लागत वसूलने के लिए। उन्होंने कहा कि डिस्काम को समझना होगा कि ईवी उनके लिए एक बड़ा राजस्व क्षेत्र बनेगा, न कि केवल उद्योग। सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बिजली कनेक्शन लागत के लिए बजट प्रावधान किए हैं, लेकिन इस आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा उपयोग ही नहीं हुआ है, जबकि सरकार आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन देने को भी तैयार है। उन्होंने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के कम उपयोग (कई स्थानों पर 1 फीसदी से भी कम) पर भी चिंता जताई, जिससे रखरखाव प्रभावित होता है और कई स्टेशन बेकार हो जाते हैं। कपूर ने सुझाया कि चार्जिंग स्टेशन ऐसी जगहों पर हों जहां वाहन आम तौर पर देर तक रुक सकें। उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माताओं को अपने वाहनों के लिए निजी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने से बचने की सलाह दी और राजमार्गों पर सार्वभौमिक चार्जिंग सुविधा विकसित करने का आह्वान किया। सरकार इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और भारी औद्योगिक वाहनों के लिए भी चार्जिंग ढांचा खड़ा करना चाहती है, जिसके तहत बस डिपो को अन्य ईवी के उपयोग के लिए खोलने पर विचार किया जा रहा है।

वित्तीय क्षेत्र को सामूहिक साइबर सुरक्षा रणनीति अपनाने पर जोर: डीएफएस



नई दिल्ली। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और बीमा कंपनियों को अपनी साइबर सुरक्षा रणनीतियों को साझा करने और मिलकर काम करने की सलाह दी है। उन्होंने साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी को वित्तीय क्षेत्र के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि बैंक धोखाधड़ी और डेटा सेंधमारी की घटनाएं अब आम हो गई हैं। उन्होंने जोर दिया कि साइबर सुरक्षा को सामूहिक चुनौती मानते हुए, संस्थानों को अपनी सुरक्षा रणनीतियों को व्यापारिक रहस्य मानने के बजाय साझा करना चाहिए, ताकि सभी उभरते खतरों से बेहतर ढंग से निपट सकें। उन्होंने साइबर हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को एक नई चुनौती बताया। संस्थानों को साफ्टवेयर, प्रोटोकाल और मानव संसाधन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बैंकों, प्रौद्योगिकी वेंडरों और समाधान प्रदाताओं के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया गया है, जिसके लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) को पहल करने को कहा गया है। डिजिटल भुगतान और फिनटेक के विस्तार से यह क्षेत्र विकसित भारत 2047 में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसकी साइबर सुरक्षा प्राथमिकता है।

नेपाल को भारत से मिल सकता है 2 अरब डॉलर का पैकेज

रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य में समझौते, जनकपुर-अयोध्या ट्रेन को हरी झंडी

नई दिल्ली

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार से भारत की दो दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान भारत अपने पड़ोसी देश के लिए 2 अरब डॉलर के एक ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह पैकेज भारत द्वारा किसी भी पड़ोसी देश को दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सहायता पैकेज साबित हो सकता है, जो दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत है।

यह बहुप्रतीक्षित पैकेज यदि मंजूर होता है, तो भारत की ओर से अपने किसी पड़ोसी देश को दी जाने वाली सबसे बड़ी आर्थिक सहायता होगी। इस दौरान रेल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत क्षेत्रों में निवेश तथा आपसी संपर्क बढ़ाने को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिसमें दोनों देशों के विमानों को एक-दूसरे के क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति भी शामिल है। चर्चा है कि पैकेज का एक बड़ा हिस्सा अगस्त में ग्लेशियर से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल में पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की उम्मीद है, जिसमें 1,500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 7,000 से अधिक घर व कई जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं। यात्रा के दौरान नेपाल के जनकपुरधाम और अयोध्या कैंट को जोड़ने वाली साप्ताहिक सीमा पार रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी।

साथ ही, उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा में एक एकीकृत चेक पोस्ट का भी उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री शाह रविवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसके बाद वे काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे। यह शाह की प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों प्रधानमंत्री भारत-नेपाल संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, जल संसाधन और भौतिक व डिजिटल संपर्क के साथ-साथ स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और खेल जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। शाह के साथ वित्त और विदेश मंत्रियों सहित 34 सदस्यीय आधिकारिक और 52 सदस्यीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा, जो नेपाल-भारत कारोबारी फोरम की बैठक में भी भाग लेगा।



म्यूचुअल फंड में इक्विटी का जलवा, 10 साल में निवेशकों का भरोसा बढ़ा

इक्विटी और ईएलएसएस फंड का एयूएम 37 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली

भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग ने पिछले दशक में इक्विटी निवेश की ओर एक बड़ा और निर्णायक बदलाव देखा है। अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2026 के बीच, इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) फंड ने पूरे उद्योग की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विकास किया है, जो घरेलू बचत में बाजार से जुड़े निवेश की बढ़ती अहमियत को दर्शाता है। यह ट्रेंड निवेशकों के बदलते रुझान और इक्विटी बाजारों में उनके बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत है। भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में पिछले 10 वर्षों के दौरान इक्विटी निवेश में रिकार्ड उछाल आया है। अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2026 के बीच, इक्विटी और ईएलएसएस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 7.7 गुना बढ़कर 37.18 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग का कुल एयूएम 5.1 गुना बढ़कर 83.39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा।

एक विश्लेषण के मुताबिक अक्टूबर 2016 में इक्विटी और ईएलएसएस फंड का एयूएम 4.85 लाख करोड़ रुपये था, जो कुल म्यूचुअल फंड संपत्ति का 29.8 फीसदी था। अक्टूबर 2026 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 44.6 फीसदी हो गई, यानी 10 सालों में इसमें करीब 14.8 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग के एयूएम की चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) 17.7 फीसदी रही, जबकि इक्विटी और ईएलएसएस फंड का एयूएम 22.6 फीसदी की कहीं अधिक प्रभावशाली दर से बढ़ा। हालांकि, इक्विटी फंड की हिस्सेदारी में यह बढ़ोतरी सीधी नहीं रही। अक्टूबर 2018 में यह 33.4 फीसदी थी, जो अक्टूबर 2020 तक घटकर 28.5 फीसदी रह गई, लेकिन इसके बाद इसमें लगातार सुधार हुआ और अक्टूबर 2023 तक यह 40 फीसदी के पार पहुंच गई, जो अक्टूबर 2026 में 44.6 फीसदी पर स्थिर हुई। इक्विटी कैटेगरी के भीतर स्माल कैप और सेक्टोरल/थीमैटिक फंड ने सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की। अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2026 के बीच स्माल कैप फंड का एयूएम 9.2 गुना बढ़कर 4.41 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसकी सीएजीआर 37.3 फीसदी रही। इसी दौरान, सेक्टोरल और थीमैटिक फंड का एयूएम 8.3 गुना बढ़कर 5.38 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, जिसकी सीएजीआर 35.3 फीसदी रही। निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है; अक्टूबर 2019 में उद्योग के कुल फोलियो की संख्या 8.63 करोड़ थी, जो अक्टूबर 2026 तक 3.3 गुना बढ़कर 28.78 करोड़ हो गई। जानकारों का कहना है कि एयूएम में यह बढ़ोतरी सिर्फ नए निवेश के कारण नहीं है, बल्कि शेयर बाजार में शेयरों की कीमतों में हुई वृद्धि का भी इसमें अहम योगदान है।

